क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
4-0 ब्लोक, आगाम नवकार कॉम्पलेकक्ष, नीयर सचिन रेल्वे स्टेशन,सचिन, सूरत-394230
मो. 9879141480

# दैनिक क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
4-0 ब्लोक, आगाम नवकार कॉम्पलेकक्ष, नीयर सचिन रेल्वे स्टेशन,सचिन, सूरत-394230
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com

सूरत, वर्ष: 1 अंक: 217, शनिवार, 01 सितम्बर, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1


## अनुच्छेद 35ए को लेकर घाटी में दूसरे दिन भी हड़ताल

**श्रीनगर ।** सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को अनुच्छेद 35 ए पर सुनवाई के खिलाफ अलदाववादियों द्वारा आहूत हड़ताल और प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के चलते कश्मीर में दूसरे दिन भी आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। संयुक्त प्रतिरोध नेतृत्व (जेआरएल) में शामिल सैयद अली शाह गिलानीए मीरवाइज मौलवी उमर फारुक और मोहम्मद यासीन मलिक ने अनुच्छेद 35-ए को कथित रूप से कमजोर करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ गुरुवार से दो दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया। हड़ताल के आह्वान का समर्थन कारोबारियों, ट्रांसपोर्टरों, नागरिकों और धार्मिक संगठनों ने किया है। दूसरी ओर अनुच्छेद 35ए के समर्थन में अलगाववादियों की ओर से किए गए विरोध-प्रदर्शन को रोकने के लिए शुक्र वार को श्रीनगर में प्रतिबंध लगा दिया गया। पुलिस ने एक बयान में कहा कि नौहट्टा, खानयार, रैनावाड़ी, एम.आर. गंज और सफाकदल पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाए गए हैं, जबकि क्रालखोड और मैसूमा पुलिस स्टेशनों के तहत आने वाले क्षेत्रों में आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा रहेगा। पुलिस ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं।

सैयद अली गिलानी, मीरवायज उमर फारूक और मोहम्मद यासीन मलिक की अगुआई वाले की अलगाववादी धड़े संयुक्त प्रतिरोध नेतृत्व (जे.आर.एल.) द्वारा 30 अगस्त और 31 अगस्त को अनुच्छेद 35ए के समर्थन में पूरी तरह से बंद का आह्वान किया गया है।

गौरतलब है कि अनुच्छेद 35ए की संवैधानिक वैधता को याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई है। एन.जी.ओ. श्री द सिटीजन ने मुख्य याचिका 2014 में दायर की थीण्इस याचिका में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के चलते जम्मू कश्मीर के बाहर के भारतीय नागरिकों को राज्य में संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं है। वहीं कोर्ट में दायर याचिका पर अलगाववादी नेताओं ने एक सुर में कहा था कि अगर कोर्ट राज्य के लोगों के हितों के खिलाफ कोई फैसला देता है, तो जनता आंदोलन के लिए तैयार हो जाए।

रामंमदिर निर्माण के वादे की उन्हें याद तक नही

## मंदिर की बजाय ट्रिपल तलाक की पैरवी में जुटी है मोदी सरकार: तोगडिया

**जौनपुर।** अंतर्राष्ट्रीय हिन्दू परिषद (अहिप) के अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगडिया ने कहा कि अयोध्या में राममंदिर निर्माण का संकल्प लेकर सत्ता में आयी केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार करोड़ो हिन्दू जनमानस की भावनाओं पर ध्यान देने की बजाय ट्रिपल तलाक की पैरवी में जुटी है। तोगडिया ने गुरूवार देर शाम यहां पत्रकारों से कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राममंदिर निर्माण के वादे के साथ 2014 में केन्द्र की सत्ता हासिल की थी मगर हर बार की तरह इस कार्यकाल में भी भाजपा इस संवेदनशील मुद्दे को भूल गयी और अल्पसंयक समुदाय की महिलाओं के दिल में जगह बनाने के लिये ट्रिपल तलाक की जोरशोर से पैरवी करने लगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बगैर वादे के जीएसटी और ट्रिपल तलाक कानून पारित करा सकती है लेकिन जिस वादे ने उसे सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, उस राममंदिर निर्माण के वादे की उन्हें याद तक नही है। उन्होने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगर मंदिर निर्माण के लिये मार्ग प्रशस्त नही करायेंगे तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मंदिर बनाने आएंगे ।

उन्होंने साफ कहा कि सरकार किसी की भी हो राम मंदिर तो बनकर रहेगा। राम मंदिर निर्माण के लिए अहिप के कार्यकर्ता विजय दशमी के बाद 31 अक्टूबर को लखनऊ से अयोध्या कूच करेगें। इससे पहले देश के 30 करोड़ हिन्दुओ का हस्ताक्षर लेकर शपथ पत्र भरवाने का काम किया जायेगा।

## अपहरण मामलों को लेकर अलगाववादियों पर भड़के उमर , उठाए कई सवाल

**श्रीनगर ।** कश्मीर में आतंकियों का दुस्साहस बढ़ता रहा है। वे लगातार सुरक्षा बलों व पुलिसकर्मियों पर निशाना बना रहे हैं। हाल में पुलिसकर्मियों व सुरक्षा बलों को अगवा किए जाने के साथ-साथ उनके रिश्तदारों के अपहरण की वारदातें भी बढ़ी हैं, जिसे लेकर लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। इन घटनाओं ने अलगाववादियों के रवैये पर भी सवाल उठाए हैं। लगाववादी वैसे तो सुरक्षा बलों पर स्थानीय लोगों के साथ 'ज्यादती' का आरोप लगाते रहते हैं और हिंसक भीड़ व पत्थरबाजों तक से निपटने के लिए उनकी सख्ती पर सवाल उठाते रहे हैं, पर अपहरण के ऐसे मामलों पर कभी अपनी जुबान नहीं खोलते। अलगाववादियों के इस दोहरे रवैये को लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री व नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 11 अपहरण! यह घाटी में चिंताजनक हालात को दर्शाता है। लेकिन सबसे दुखद चुनिंदा मसलों का विरोध है। जो लोग और नेता सुरक्षा बलों की कथित ज्यादतियों को लेकर मुखर रहे हैं, वे इन अपहरणों पर आवाज नहीं उठाते।

## कश्मीर में दूसरे दिन भी रेल सेवा स्थगित

**श्रीनगर।** आर्टिक्ल 35ए की सुनवाई को लेकर कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आज दूसरे दिन भी रेल सेवा स्थगित रही। रेलवे अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को घाटी में सभी रेल सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया। रेल संपत्ति की सुरक्षा को देखते हुये यह निर्णय लिया गया। जानकारी के अनुसार मध्य कश्मीर में श्रीनगर से बडगाम और नाथ में बारामूला तक सभी ट्रेनें बंद रहीं। वहीं श्रीनगर-अनंतनाग-काजीगुंड और जम्मू के बनिहाल में भी ट्रेन सेवा स्थगित है। घाटी में प्रदर्शनों के दौरान रेल संपत्ति को भी निशाना बनाया जाता है। 2016 में बुरहान वानी की मौत के बाद घाटी में जो हालात पैदा हुये थे, उस दौरान रेल संपत्ति को काफी नुकसान हुआ था।

## यूजीसी का फरमान,निकाले जाएंगे 80 हजार से अधिक फर्जी शिक्षक

**मथुरा।** देश के उच्च शिक्षण संस्थानों के मानक तय करने वाली सर्वोच्च संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पाया है कि राज्य स्तरीय तथा निजी विश्वविद्यालयों में 80 हजार शिक्षक सिर्फ कागजों पर काम कर रहे हैं। ये फर्जी शिक्षक बनावटी आधार पर पूर्णकालिक शिक्षकों के तौर पर कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2016-17 के सर्वे से प्राप्त हुए आंकड़ों के आधार पर राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के उच्च शिक्षण संस्थानों में जगह पाए इन प्रतिनिधि शिक्षकों को निकाल बाहर करने के लिए राज्यों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। यह जानकारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन प्रो. धीरेंद्र पाल सिंह ने आज यहां दी। वह पं. दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विवि एवं गौ अनुसंधान संस्थान के आठवें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया, ''यह सही है कि जिस प्रकार अब तक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में फर्जी शिक्षकों की भर्ती की शिकायतें मिलती रही हैं, उसी प्रकार उच्च शिक्षा में भी अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण 2016-17 में 80 हजार से अधिक प्रॉक्सी टीचर्स की जानकारी सामने आई है।'' उन्होंने बताया, ''इनसे मुक्ति के लिए राज्यों को एक विशेष निर्देश जारी कर उनके आधार कार्ड आदि ठोस पहचान पत्रों के आधार पर उनकी पहचान कर सिस्टम से निकाल बाहर करने को कहा गया है।'' उनके इस जवाब की पुष्टि राज्यपाल राम नाईक ने भी मीडिया से वार्ता में की है। उन्होंने माना कि ऐसा पाया गया है कि निचली कक्षाओं के समान ही अब उच्च शिक्षण संस्थानों में भी बड़ी संख्या में शिक्षक गलत तरीके अपनाकर जगह पा गए हैं। लेकिन अब सरकार उन सबके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने जा रही है। प्रो. सिंह ने उच्च शिक्षा का स्तर एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आयोग द्वारा की गई की अन्य पहलों के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया, ''अब भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर नए शिक्षण संस्थानों में शिक्षक बनने वाले अर्भ्यिथयों को भी पहले एक माह खुद विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी होगा। जिससे वे खुद भी क्षेत्र एवं विषय-विशेष के बारे में पढ़ाने में पूर्ण सक्षम हो जाएं। अपडेट हो जाएं।'' आयोग के अध्यक्ष ने बताया, ''जो विवि विगत वर्षों में गुणवत्ता के मामले में अव्वल पाए गए हैं उनका अपग्रेडेश किया जाएगा तथा उन्हें स्वायत्तता देने में पहल की जाएगी। जिससे वे एक स्वायत्तशासी संगठन के समान आगे बढने् के संबंध में निर्णय लेने में सक्षम हो।

## चंडीगढ़ ऑटो गैंगरेप मामला: तीनों दोषियों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

**चंडीगढ़(सुशिल) ।?** बीते वर्ष के नवंबर महीने में सैक्टर-53 में युवती से गैंगरेप मामले के तीनों दोषियों को अदालत ने आज उम्रकैद हुई हैं। दोषियों में मूलरूप से अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश निवासी मोहम्मद इरफान (29), किस्मत अली उर्फ पोपू (23) और मोहम्मद गरीब (23) शामिल हैं। अदालत ने मामले के ट्रायल का 118 दिन में निपटारा करते हुए बीते सोमवार को उक्त तीनों को दोषी करार दिया था। दोषियों ने मूलरूप से देहरादून निवासी एवं मोहाली में बतौर पी.जी रहने वाली 21 वर्षीय युवती से दुराचार किया था। सैक्टर -36 थाना पुलिस ने तीनों दोषियों के खिलाफ आई.पी.सी.-376-डी, 376-2 और आई.पी.सी.-506 के तहत केस दर्ज किया था, लेकिन पुलिस ने दोषियों के खिलाफ दायर चार्जशीट से आई.पी.सी 376-2 को हटा सजा के लिए आई.पी.सी-376-डी व 506 में चार्जशीट दायर की थी। अदालत ने इन्हीं धाराओं के तहत ट्रायल शुरू किया था। दोषियों की डीएनए रिपोर्ट भी पॉजीटिव आई थी। पीड़िता ने भी दोषियों को अदालत में पहचानते हुए उनके खिलाफ बयान दिए थे। पीड़िता सेक्टर 37 कोचिंग सेंटर से मोहाली पीजी जाने के लिए निकली थी।

उसने ऑटो लिया, उसमें दो सवारियां पहले से बैठी थीं। मौका मिलते ही ड्राइवर और दोनों युवकों ने उसे दबोच लिया और सेक्टर 53 में जंगल में ले जाकर उस से गैंगरेप किया।

फिर वे उसे जान से मारने की धमकी देते हुए सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हो गए।

## एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में चिदंबरम से फिर हुई पूछताछ

**नई दिल्ली।** प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एयरसेल-मैक्सिस मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से आज फिर पूछताछ की। अधिकारियों ने आज यह जानकारी दी। उसने कहा कि चिदंबरम सुबह ईडी के दफ्तर पहुंचे। मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के तहत उनके बयान को रिकार्ड किया जाएगा। यह चौथा मौका है जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से पूछताछ की गई। इससे पहले, उनसे 24 अगस्त को करीब छह घंटे तक पूछताछ की गई थी। चिदंबरम के बेटे कार्ति से ईडी ने दो बार पूछताछ की है। सीबीआई ने जुलाई में इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था।

ईडी अगले पखवाड़े इस संबंध में अभियोजन पत्र दायर कर सकता है। एयरसेल-मैक्सिस मामला विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा मेसर्स ग्लोबल कम्युनिकेशन होल्डिंग सर्विसेज लि. को एयरसेल में निवेश की मंजूरी से जुड़ा है। उच्चतम न्यायालय ने 12 मार्च को जांच एजेंसियों सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय को एयरसेल मैक्सिस मामले में कथित मनी लांड्रिंग समेत 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन मामले में छह महीने में जांच पूरी करने को निर्देश दिया था। एजेंसी ने कहा था कि एयरसेल-मैक्सिस एफडीआई मामले में एफआईपीबी मंजूरी मार्च 2006 में चिदंबरम ने दी थी। हालांकि, वह केवल 600 करोड़ रुपए तक के निवेश को ही मंजूरी दे सकते थे।

संक्षिप्त समाचार

## मेनका ने मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र: महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए बने संयुक्त आश्रय केंद्र

**मथुरा/वृंदावन।** केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वे अपने यहां बेसहारा महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए संयुक्त आश्रय केंद्र के लिए पहल करें ताकि इनकी सही ढंग से निगरानी हो सके और मुजफ्फरपुर जैसी घटना नहीं हो। वृंदावन में विधवा एवं बेसहारा महिलाओं के लिए आश्रय गृह 'कृष्ण कुटीर' का उद्घाटन करने के बाद मेनका ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने संयुक्त आश्रय केंद्र को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा,''मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा है कि वे बेसहारा महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए एक संयुक्त आश्रय स्थल के लिए जमीन दें। अगर एक आश्रय स्थल में सभी होंगे तो इनकी सही ढंग से निगरानी हो सकेगी। इससे मुजफ्फरपुर जैसी घटना को रोका जा सकेगा। इससे पहले मेनका और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने'कृष्ण कुटीर'का उद्घाटन किया। उन्होंने संयुक्त आश्रय स्थल के लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से लखनऊ और वाराणसी में जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया जिस पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 'स्वाधार गृह' योजना के तहत वृंदावन में बनाए गए 'कृष्ण कुटीर' में करीब एक हजार विधवाएं रह सकेंगी। इसका निर्माण एनबीसीसी के द्वारा 1.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में किया गया है और इस पर 57 करोड़ रुपये का खर्च आया है। इस चार मंजिला इमारत को बुजुर्गों और दिव्यांगों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें कौशल-सह-प्रशिक्षण केंद्र भी होगा।

## उत्तर कश्मीर के जंगलों में सुरक्षा बलों ने किया तलाशी अभियान , 2 जवान घायल

**श्रीनगर ।** उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के जंगलों में आंतकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान सेना के दो जवान घायल हो गये। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बांदीपुरा के चनादजन के जंगलों में आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों और जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) ने संयुक्त रूप से घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि जंगल से गोलियों की आवाज सुनायी दी। अंतिम रिपोर्ट मिलने तक पूरे जंगली इलाके की घेराबंदी की गयी और सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में बांदीपुरा जिले में हाजिन इलाके में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के दो विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया था।

## भाजपा के चाइनीज गांधी बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा- आपको पाप लगेगा

**नई दिल्ली।** कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। जहां भाजपा ने राहुल के चीन के रास्ते से कैलाश यात्रा पर जाने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष को चाइनीज गांधी कहा है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा पर पहलटवार करते हुए कहा कि क्या महादेव के दर्शन करने जाने के लिए राहुल को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इजाजत लेनी पड़ेगी। सुरजेवाला ने कहा कि जो भी भगवान भोलेनाथ और उनके भक्तों के बीच आता है उनको पाप और श्राप लगता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राहुल देश की उन्नति और विकास की कामना के लिए कैलाश यात्रा कर रहे हैं लेकिन भाजपा उनके खिलाफ षडयंत्र कर रही है। सुरजेवाला ने कहा कि धार्मिक यात्रा पर ओछी साजिश भाजपा को मुबारक हो। उल्लेखनीय है कि आज भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेस करके राहुल पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें चाइनीज गांधी बताया। पात्रा ने कहा कि राहुल को चीन से इतना प्रेम क्यों है। जब राहुल जर्मनी दौरे पर गए थे तब भी उन्होंने वहां भारत की बजाए चीन का ही गुणगान किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी के जरिए देश को ''वित्तीय अराजकता'' में डालने के लिए कौन-सा प्रायश्चित करेंग

# शिवसेना का मोदी पर हमला, कहा- लोकप्रियता हासिल करने के लिए की गई नोटबंदी

**मुंबई।** शिवसेना ने आरबीआई की एक रिपोर्ट के मद्देनजर आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी के जरिए देश को ''वित्तीय अराजकता'' में डालने के लिए कौन-सा प्रायश्चित करेंगे। दरअसल, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चलन से बाहर किए गए 99. 3 प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस लौट आए हैं। शिवसेना ने कहा कि नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया, उद्योग प्रभावित हुए, आजादी के बाद से पहली बार रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया और सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन अब भी देश के शासक विकास की शेखी बघार रहे हैं। पार्टी के मुखपत्र 'सामना' में आज एक संपादकीय में कहा गया है, ''चूंकि नोटबंदी ने देश को वित्तीय अराजकता में डाल दिया, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से किए गए वादों को लेकर कौन-सा प्रायश्चित करेंगे? नोटबंदी की कवायद लोकप्रियता हासिल करने के लिए की गई।'' उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी नवंबर 2016 में गोवा में दिए मोदी के भाषण का जिक्र कर रही थी, जहां प्रधानमंत्री ने लोगों से 50 दिन तक उनके साथ सहयोग करने की अपील की थी और कहा था कि यदि उनके इरादे गलत पाए गए तो वह देश द्वारा दी जाने वाली कोई भी सजा भोगने को तैयार हैं। शिवसेना ने कहा कि नोटबंदी ने देश के लिए परेशानियां खड़ी की। पार्टी ने कहा, ''देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े फैसले जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। नोटबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, जिस पर रिजर्व बैंक ने भी मुहर लगाई।'' पार्टी ने कहा, ''मोदी ने कहा था नोटबंदी का मतलब भ्रष्टाचार, काला धन और जाली नोटों को हमेशा के लिए खत्म करना है। हालांकि, पिछले दो वर्षों में ये सभी चीजें बढ़ गई। ये दावे भी खोखले साबित हुए कि नोटबंदी से कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां खत्म हो जाएंगी और घाटी में शांति स्थापित होगी।'' पार्टी ने कहा कि काला धन और जाली नोट हासिल नहीं किए जा सकें क्योंकि 99.3 प्रतिशत नोट बैंकिंग व्यवस्था में वापस आ गए। भाजपा के सहयोगी दल शिवसेना ने कहा कि नोटबंदी के कारण छोटे उद्योग, आवासीय एवं सेवा क्षेत्र बर्बाद हो गए, किसानों को काफी सहन करना पड़ा और लोगों को दो महीनों तक बैंकों के बाहर लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ा। पार्टी ने दावा किया कि इन कतारों में 100 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पार्टी ने आरोप लगाया कि नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ कर रख दी। सरकारी खजाने को नए नोट छापने में 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एटीएम में तकनीकी बदलावों पर 700 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। नए नोटों के वितरण पर भी 2,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। पार्टी ने कहा कि नोटबंदी का कदम बहुत ही भयावह था जिससे 2.25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शिवसेना ने कहा, ''यह सरकारी खजाने की लूट है। आरबीआई गवर्नर ने इस लूट को रोका नहीं, जिसके लिए उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाना चाहिए। आरबीआई का काम अर्थव्यवस्था की रक्षा करना है और मौजूदा सरकार में वह मतवाले बंदर की तरह हो गया है।''

पार्टी ने कहा कि मूलतः कालेधन का कोई अंबार नहीं लगाता और नोटबंदी से यह पैसा खत्म नहीं हो सकता, यह बहुत ही आसान-सा अर्थशास्त्र है। जिनकी समझ में यह नहीं आया उन्होंने पूर्व मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाया, मगर अब सच सामने आ गया है।''

संपादकीय

## नोटबंदी का नतीजा

नोटबंदी पर रिजर्व बैंक की बहुप्रतीक्षित रपट आने के बाद विपक्षी दलों समेत अन्य आलोचकों की ओर से सरकार को घेरना स्वाभाविक ही है। रिजर्व बैंक के अनुसार नोटबंदी के समय देश भर में पांच सौ और एक हजार के कुल 15 लाख 41 हजार करोड़ रुपये के नोट चलन में थे, लेकिन उनमें से 15 लाख 31 हजार करोड़ रुपये के नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए। इसका मतलब है कि करीब दस हजार करोड़ रुपये ही वापस नहीं आ सके। यह कोई बड़ी रकम नहीं। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि दावा तो यह किया गया था कि कालेधन के रूप में लगभग ढाई-तीन लाख करोड़ रुपये बैंकों में लौटने वाले नहीं और वे रद्दी हो जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ तो इसका एक बड़ा कारण यह रहा कि बैंकिंग तंत्र ने कालेधन वालों से मिलीभगत कर ली। हैरानी है कि इतना बड़ा फैसला लेने के पहले किसी ने यह क्यों नहीं सोचा कि कहीं बैंक कर्मी सारी मेहनत पर पानी न फेर दें? आखिर इसे लेकर कोई सही आकलन क्यों नहीं किया जा सका कि लोग अपने कालेधन को सफेद बनाने के लिए क्या-क्या जतन कर सकते हैं? अच्छा होगा कि सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया जाए कि जब दस हजार करोड़ रुपये छोड़कर सारी रकम बैंकों में आ गई तो नोटबंदी को सफल कैसे कहा जा सकता है? चूंकि करीब इतनी ही रकम नए नोट छापने और उन्हें देश के सभी इलाकों में भेजने में खर्च हो गई इसलिए इस पर आश्चर्य नहीं कि नोटबंदी को व्यर्थ की कसरत बताया जा रहा है। ध्यान रहे कि नोटबंदी से नकली नोटों के साथ ही आतंकी एवं नक्सली गुटों पर लगाम लगने के दावे भी बहुत पुख्ता नहीं कहे जा सकते। करदाताओं की संख्या में वृद्धि को नोटबंदी की एक सफलता के तौर पर अवश्य रेखांकित किया जा सकता है, लेकिन सभी जानते हैं कि यह इस फैसले का मूल मकसद नहीं था। मूल मकसद तो कालेधन वालों की कमर तोड़ना था। 1नोटबंदी पर विपक्ष के तीखे सवालों के बीच सरकार की ओर से एक बार फिर यह कहा गया कि बैंकों में जमा हो गए सारे धन को सफेद नहीं कहा जा सकता और करीब 18 लाख जमाकर्ता संदिग्ध किस्म के पाए गए हैं। ये वे लोग हैं जिनसे यह पूछा जा रहा है कि उन्होंने बैंक में जमा अपना पैसा कैसे अर्जित किया? सरकार की मानें तो इनमें से तमाम से टैक्स और जुर्माना वसूल किया जा रहा है। बेहतर हो कि सरकार की ओर से यह साफ किया जाए कि अब तक टैक्स और जुर्माने से कितनी राशि वसूल की जा चुकी है और सभी संदिग्ध खाताधारकों की जांच-पड़ताल कब तक पूरी हो जाएगी? यह ठीक है कि 18 लाख लोगों से जवाब-तलब एक बड़ा काम है, लेकिन यह प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए और इसमें वैसी देर नहीं होनी चाहिए जैसी नोटबंदी पर रिजर्व बैंक की रपट सामने आने में हुई। नोटबंदी जितना अप्रत्याशित उतना ही बड़ा फैसला था। चूंकि इस फैसले ने हर एक पर असर डाला इसलिए सरकार को हर तार्किक सवाल का संतोषजनक जवाब देना चाहिए।

# डर कौन रहा है?

चुनावी खर्च/ राजेन्द्र शर्मा

*प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसीलिए तो छाती ठोक कर कहते हैं कि उन्हें बड़े पूंजीपतियों से अपने रिश्तों को छुपाने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती है। बहरहाल, दुनिया भर में जनतांत्रिक व्यवस्था में किसी-न-किसी रूप में चुनाव में धनबल के दखल पर अंकुश लगाने की कोशिश की जाती है, वरना धनबल जनतंत्र को धनिकों के अल्पतंत्र में ही तब्दील कर देगा। उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा लगाने के जरिए, देश में भी कम-से-कम सैद्धांतिक स्तर पर तो यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया ही जाता है कि धन के बल पर चुनाव नहीं जीते जाने चाहिए। लेकिन इस व्यवस्था में एक बड़ा छेद यह है कि उम्मीदवारों के लिए तो चुनावी खर्च की सीमा तय की गई है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को इसकी छूट है कि वे अपनी ओर से चुनाव पर कितना भी खर्च कर सकती हैं।*

अगले आम चुनाव की अपनी तैयारियों की बाकायदा शुरुआत का संकेत करते हुए चुनाव आयोग द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में, ईवीएम मशीनों की उपयुक्तता के मुद्दे से ज्यादा जोर से राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव पर किए जाने वाले खर्च पर सीमा लगाए जाने का मुद्दा उठा। महत्त्वपूर्ण है कि इस मसले पर, सत्ताधारी भाजपा को छोड़कर, देश की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ खड़ी दिखाई दीं। उनके अनुसार उम्मीदवारों की ही तरह, राजनीतिक पार्टियों के लिए भी चुनाव खर्च की सीमा तय किया जाना, चुनाव में खास तौर पर राजनीतिक पार्टियों के लिए बराबरी के मौके सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। सत्ताधारी भाजपा इस मुद्दे पर एकदम अलग-थलग पड़ गई है। यहां तक कि एनडीए के उसके कई सहयोगी दल भी इस मामले में उसके साथ खड़े होने से कतरा रहे हैं।भाजपा अगर अलग-थलग पड़ने का जोखिम उठाकर भी इस तरह की सीमा लगाए जाने के विचार तक का विरोध कर रही है, तो इसका कारण समझना कोई मुश्किल नहीं है। सभी जानते हैं कि भाजपा न सिर्फ देश की सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी बन चुकी है, बल्कि 2014 के आम चुनाव में जीत से काफी पहले ही यह हैसियत हासिल कर चुकी थी। 2014 के चुनाव में भाजपा ने न सिर्फ तब तक सत्ताधारी कांग्रेस के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसा लगाया था, वास्तव में इस चुनाव से उसने देश को बेतहाशा महंगे चुनावों के दौर में धकेल दिया है। संयोग ही नहीं है कि खुद राजनीतिक पार्टियों द्वारा आयकर अधिकारियों को दिए गए विवरण पर आधारित, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, 2016-17 में भाजपा ने आधिकारिक रूप से 1,034.27 करोड़ रुपये की आय दर्ज कराई थी, जबकि इस वर्ष में सभी सात राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों की कुल आय, 1,559.17 रुपये रही थी। यह भी गौरतलब है कि 2015-16 और 2016-17 के बीच भाजपा की आय में पूरे 81.18 फीसद की बढ़ोतरी हुई थी और उसकी आय 570.86 करोड़ रुपये से बढ़कर 1034.27 करोड़ के अंक पर पहुंच गई, जबकि इसी अवधि में कांग्रेस की आय 14 फीसद की गिरावट के साथ, 261.56 करोड़ रुपये से घटकर 225.36 करोड़ रुपये पर आ गई। एडीआर की उक्त रिपोर्ट का ही एक और आंकड़ा चुनाव के संदर्भ में और भी प्रासंगिक है। इस एक वर्ष के दौरान ही भाजपा ने चुनाव और आम प्रचार पर पूरे 606.64 करोड़ रुपये खर्च किए थे, जबकि उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस इसी दौरान हुए चुनावों पर इससे चौथाई यानी कुल 149.65 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाई थी। पैसा खर्च करने की ताकत भाजपा के हाथों में एक बड़ा चुनावी हथियार बन गई है, जो उसे दूसरी पार्टियों के मुकाबले में बढ़त दिलाता है। अचरज की बात नहीं है कि भाजपा को और जाहिर है कि उसके पीछे खड़े संघ परिवार को ही, पैसे के बल पर हासिल होने वाली इस बढ़त में कुछ भी अनुचित दिखाई नहीं देता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसीलिए तो छाती ठोक कर कहते हैं कि उन्हें बड़े पूंजीपतियों से अपने रिश्तों को छुपाने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती है। बहरहाल, दुनिया भर में जनतांत्रिक व्यवस्था में किसी-न-किसी रूप में चुनाव में धनबल के दखल पर अंकुश लगाने की कोशिश की जाती है, वरना धनबल जनतंत्र को धनिकों के अल्पतंत्र में ही तब्दील कर देगा। उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा लगाने के जरिए, देश में भी कम-से-कम सैद्धांतिक स्तर पर तो यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया ही जाता है कि धन के बल पर चुनाव नहीं जीते जाने चाहिए। लेकिन इस व्यवस्था में एक बड़ा छेद यह है कि उम्मीदवारों के लिए तो चुनावी खर्च की सीमा तय की गई है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को इसकी छूट है कि वे अपनी ओर से चुनाव पर कितना भी खर्च कर सकती हैं। राजनीतिक पार्टियों के लिए यह सीमाहीन छूट, उम्मीदवारों के खर्च की सीमा को व्यवहार में निर्थक ही बना देती है। राजनीतिक पार्टियों के नाम पर चुनाव में असीमित खर्चों पर अंकुश लगाने का एक आसान उपाय तो यही हो सकता है कि राजनीतिक पार्टी के खर्चे में से चुनाव क्षेत्र विशेष का हिस्सा, उम्मीदवार के खर्चे में जोड़ दिया जाए। इसके लिए अगर जरूरी हो तो उम्मीदवारों के खर्च की सीमा में कुछ बढ़ोतरी भी की जा सकती है। लेकिन इसमें किसी बहस की गुंजाइश नहीं है कि सिर्फ उम्मीदवार के खर्च पर अंकुश लगाना और राजनीतिक पार्टियों को कितना भी खर्च करने की छूट देना, चुनाव में धनबल के दखल पर अंकुश लगाने की पूरी कवायद को ही बेमानी बना देता है। याद रहे कि मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि आज भाजपा को, चुनाव में पैसा खर्च करने के लिहाज से दूसरी सभी पार्टियों के मुकाबले भारी बढ़त हासिल है। मुद्दा सिर्फ इतना भी नहीं है कि भाजपा आज देश के बड़े धनपतियों की सबसे चहेती पार्टी बनी हुई है और उन्होंने भाजपा के लिए अपने खजाने खोल दिए हैं। असली मुद्दा यह है कि बड़े धन-पतियों के किसी पार्टी के लिए इस तरह अपने खजाने खोलने का और इस धन बल के सहारे हासिल हुई सत्ता का संबंधित पार्टी द्वारा उनका यह कर्ज उतारने के लिए इस्तेमाल किए जाने का, सीधा संबंध होता है। बेशक, कांग्रेस जैसी दूसरी पार्टियां भी इस तरह के लेन-देन से कोई अछूती नहीं रही हैं। फिर भी मोदी और शाह की भाजपा, इस रिश्ते को सबसे निर्द्वंद्व रूप में व्यक्त करती है। इतना ही नहीं, मोदी के राज के लगभग साढ़े चार साल में, राजनीतिक पार्टियों के लिए चंदे से संबंधित कानूनों में चोर दरवाजे से किए गए बदलावों के जरिए, विदेशी कंपनियों के लिए राजनीतिक चंदे देने की छूट देने से लेकर, बांड के जरिए चंदे की व्यवस्था के माध्यम से राजनीतिक चंदों की समूची प्रक्रिया को ही सार्वजनिक छानबीन के दायरे से बाहर कर देने के जरिए, न सिर्फ मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के हाथों में धनबल और बढ़ाया गया है, उसे और ज्यादा उपकृत कर के, उसकी सरकार के बड़े धनपतियों की और सेवा करने का बीमा भी कराया गया है। जनतंत्र की रक्षा के लिए, धनबल के बढ़ते दखल पर अंकुश लगाना ही होगा। पार्टियों के चुनावी खर्च को सीमित करना, इस दिशा में आवश्यक चुनावी सुधारों की लंबी श्रृंखला का पहला कदम है। इस पहले कदम को अब और टाला नहीं जा सकता है। चुनाव आयोग को इस न्यूनतम चुनावी सुधार के मामले में सत्ताधारी पार्टी को वीटो का अधिकार नहीं देना चाहिए।

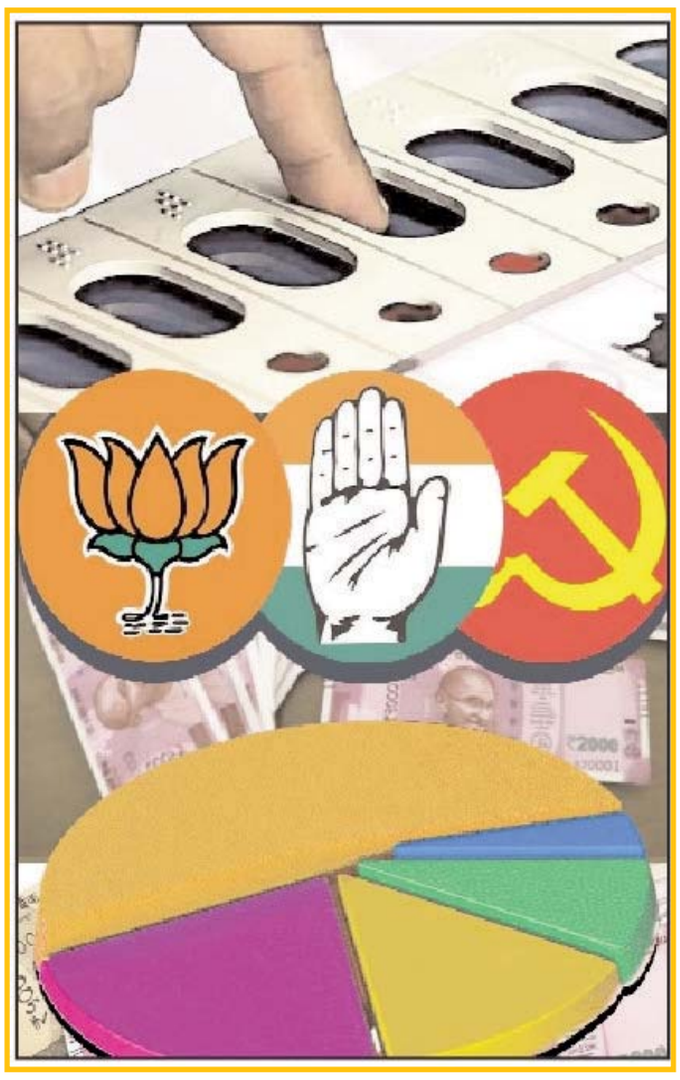

## आज का राशीफल

**मेष** गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कार्यक्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। व्यर्थ के कार्यो में धन खर्च करने के योग हैं। राजनैतिक दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे।

**वृषभ** पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। रुपए पैसे के लेन-देन में सावधानी रखें। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें।

**मिथुन** आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ होंगे। किसी अभिन्न मित्र या रिश्तेदार से मिलाप की संभावना है।

**कर्क** बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। पारिवारिक जनों से पीड़ा मिलने के योग हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। प्रणय संबंध मधुर होंगे।

**सिंह** व्यावसायिक योजना सफल होगी। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। मकान सम्पत्ति व वाहन की दिशा में किया गया प्रयास सफल होगा।

**कन्या** रोजी रोजगार की दिशा में सफलता के योग हैं। सृजनात्मक कार्यों में हिस्सा लेना पड़ सकता है। खान-पान में संयम रखें। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। दूसरों से सहयोग लेने में सफल रहेंगे।ड्ड

**तुला** शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। अपनों का सहयोग मिलेगा। वाणी की सौम्यता आपको धन लाभ करायेगी। व्यर्थ की भागदौड़ होगी।

**वृश्चिक** व्यावसायिक योजना सफल होगी। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। आर्थिक उन्नति होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

**धनु** पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। व्यावसायिक योजना सफल होगी। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा।

**मकर** बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। नेत्र विकार की संभावना है। अनावश्यक व्यय का सामना करना पड़ेगा।

**कुम्भ** दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। खान-पान संयम रखें। आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। विरोधियों का पराभव होगा।

**मीन** जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। संतान के कारण चिंतित रहेंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ होंगे। रुका हुआ कार्य सम्पन्न होगा।

# देश के निर्माताओं की उम्मीद के विपरीत बनता 'नया भारत'

ए के भट्टाचार्य

*खासतौर पर तेजी से बढ़ते मध्य वर्ग के बीच। आर्थिक अधिकार और वृद्धि से लाभान्वित होने वाला वर्ग भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। अधिकांश मध्यवर्गीय परिवारों में होने वाली चर्चा चौंकाने की हद तक अल्पसंख्यकों के बरअक्स बहुसंख्यकों के दबदबे की बातों से भरी रहती है। यह विडंबना ही है कि एक देश एक कर के लुभावने नारे के साथ देश में वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत करने वाले देश में अल्पसंख्यकों को अलग-थलग करने और बहुसंख्यकवाद के दबदबे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जिस नए भारत का चौतरफा शोर सुनाई दे रहा है वह जाति, धर्म और संप्रदाय आदि को लेकर समावेशी नहीं है।*

इस मामले में स्कूल का नाम लिया जाना उचित नहीं होगा लेकिन करीब दो सप्ताह पहले राजधानी दिल्ली के एक स्कूल में घटी घटना बताती है कि देश की राजनीति किस कदर ध्रुवीकृत हो चुकी है और सामाजिक माहौल कितना संवेदनशील हो चुका है। ध्यान रहे कि यह घटना देश की राजधानी के स्कूल की है, किसी दूरदराज ग्रामीण इलाके की नहीं। चार किशोरों ने 14 अगस्त को अपनी कक्षा में एक झंडा बनाया था। यह पाकिस्तान का झंडा था। संयोग से 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस भी था। कक्षाध्यापक ने इसकी जानकारी प्रधानाध्यापिका को दी। बच्चों से सवाल किए गए और पता चला कि उनमें से एक मुस्लिम था। इस बात ने घटना को एक नया मोड़ दे दिया और प्रधानाध्यापिका ने बच्चों को चेतावनी जारी कर दी। यहां इस घटना का जिक्र करना दो मायने रखता है। पहला, यह बताता है कि देश के स्कूलों में शिक्षा का स्तर कितना दयनीय है और दूसरा यह शायद बताता है कि देश का मध्य वर्ग किस हद तक ध्रुवीकृत हो चुका है। यह कहना शायद सही होगा कि सामाजिक मूल्यों में यह गिरावट ऐसी ही या अधिक गहन घटनाओं के वक्त राज्य की ओर से अपर्याप्त प्रतिक्रिया की वजह से आई है। बल्कि यह एक तरह के कच्चे राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली बात हो सकती है। यानी जो लोग बहुसंख्यक समाज की विश्व दृष्टि से सहमत नहीं हों उन्हें अलग-थलग कर दिया जाए या उनके साथ असहिष्णुता बरती जाए।आखिर शिक्षक इस नतीजे पर क्यों पहुंचे कि बच्चों ने कक्षा में जो झंडा बनाया है वह आपत्तिजनक है? उन्हें क्यों लगा कि इस घटना को प्रधानाध्यापिका के संज्ञान में लाया जाना चाहिए? अगर बच्चों ने पाकिस्तान के स्वाधीनता दिवस के दिन उसका झंडा बना भी दिया तो इसमें गलत क्या था? क्या शिक्षक भी राष्ट्रवाद की गलत परिभाषा के शिकार हैं? क्या शिक्षक और प्रधानाध्यापिका इस मौके का इस्तेमाल बच्चों को पड़ोसी राष्ट्र के बारे में और जानकारी देने के लिए नहीं कर सकते थे? ऐसा न करके क्या उन्होंने शिक्षा के व्यापक लक्ष्यों में से एक गंवा नहीं दिया? यकीनन शिक्षकों की प्रतिक्रिया बताती है कि उन्मादी राष्ट्रवाद के जाल में फंस जाना कितना आसान है। इसके साथ ही यह भी कि जिज्ञासा को बढ़ावा देने और ज्ञान की भूख किस कदर कम होती जा रही है? इसे यह संकेत भी मिलता है कि कैसे भारतीय समाज निम्नतम स्तर के ध्रुवीकरण का शिकार होता जा रहा है। उन बच्चों को पाकिस्तान का झंडा बनाने की प्रेरणा चाहे जैसे भी मिली हो, उस पर जो प्रतिक्रिया दी गई वह उन्हें हमेशा के लिए भयभीत कर देगी। दुनिया को देखने का उनका नजरिया बदल जाएगा। वे सभी गलत झूठे राष्ट्रवाद के शिकार हैं जिसकी एक समावेशी, स्वतंत्र और सहिष्णु समाज में कोई जगह नहीं। केवल शिक्षकों को दोष क्यों देना? एक सहयोगी का हालिया अनुभव भी देश के मौजूदा हालात के बारे में बताता है। एक पुलिस मंजूरी प्रमाणपत्र के सिलसिले में उसके घर आए पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसका काम बहुत कठिन हो गया है क्योंकि बांग्लादेश समेत विभिन्न देशों के अवैध प्रवासी बहुत बड़ी तादाद में देश में आ गए हैं। परंतु अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि लोगों के नाम और उनका रहन-सहन भी यह बता देता है कि वे अवैध प्रवासी हैं या नहीं। जाहिर है किसी को अवैध प्रवासी बताने का यह तरीका निहायत भौंडा तरीका है जो देश के कमजोर वर्ग का केवल इसलिए शोषण कर सकता है क्योंकि शायद उनका धर्म हिंदू न हो या उनके नाम उन लोगों जैसे हों जो बांग्लादेश में रहते हैं। क्या देश के नागरिकों की पहचान के बेहतर तरीके हमारे पास नहीं हैं? परंतु एक ऐसे देश में जहां असम जैसे देश में नागरिकों की राष्ट्रीय नागरिक पंजी बनाना राजनीतिक मोलभाव की वजह बन सकता है और अन्य राज्य उसकी मांग कर सकते हैं, वहां कानून प्रवर्तन एजेंसियों का यह रुख कतई चौंकाने वाला नहीं है। परंतु इससे भारतीय समाज का भला नहीं बल्कि नुकसान ही होता है। यह देश के संस्थापकों की उम्मीद से एकदम परे हैं। उन्होंने यही सोचा था कि देश का हर नागरिक जाति, धर्म आदि से परे समान अधिकार और स्वतंत्रता के साथ रह सकेगा। समावेशी भारत के स्वप्न में यह बात शामिल थी। परंतु देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज जैसी बातें कर रहा है उसे देखकर आश्चर्य होता है कि क्या समावेशी भारत की राह में गंभीर बाधा खड़ी हो चुकी है। इसके लिए आप बहुसंख्यक वाद और केंद्र के सत्ताधारी दल की ध्रुवीकरण की राजनीति को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। परंतु चिंतित करने वाली बात यह भी है कि ऐसी राजनीति को समाज के एक बड़े तबके का समर्थन मिल रहा है। खासतौर पर तेजी से बढ़ते मध्य वर्ग के बीच। आर्थिक अधिकार और वृद्धि से लाभान्वित होने वाला वर्ग भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। अधिकांश मध्यवर्गीय परिवारों में होने वाली चर्चा चौंकाने की हद तक अल्पसंख्यकों के बरअक्स बहुसंख्यकों के दबदबे की बातों से भरी रहती है। यह विडंबना ही है कि एक देश एक कर के लुभावने नारे के साथ देश में वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत करने वाले देश में अल्पसंख्यकों को अलग-थलग करने और बहुसंख्यकवाद के दबदबे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जिस नए भारत का चौतरफा शोर सुनाई दे रहा है वह जाति, धर्म और संप्रदाय आदि को लेकर समावेशी नहीं है। सन 2022 में देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के पहले हमें हालात में सुधार करने की अत्यंत आवश्यकता है। तभी हम उसे गर्व और संतुष्टि के साथ मना सकेंगे।

विचार मंथन

## विरोध को जगह देकर ही चल पाएगा यह लोकतंत्र

बद्री नारायण, प्रोफेसर, जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान

लोकतंत्र का विस्तार और उसका गहन होना इस बात पर टिका होता है कि वह कितने संवेदनशील ढंग से अपने समाज व जनता की असहमतियों, उनके प्रतिरोधों को सुनता-समझता है, उनसे संवाद करता है, उन्हें अपनी नीतियों, अपने नियमों और कार्यों में जगह देता है। बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के मामले में एक महत्वपूर्ण सुझाव टिप्पणी के रूप में सरकार को दिया है। अदालत ने कहा है कि असहमतियों और विरोधों को जगह दें, नही तो असंतोष इकट्ठा होकर वैसे ही फट सकता है, जैसे ज्यादा देर बंद करने पर प्रेशर कुकर फट जाता है। यह चेतावनी और सुझाव लोकतंत्र के लिए बहुत मूल्यवान है। वाद-विवाद, संवाद, असहमतियां, प्रतिरोध सबको सुनकर, समझकर, जगह देकर ही लोकतंत्र शक्तिवान होता है। नहीं तो उसका विकास जड़ हो जाता है, जो आगे चलकर सत्ता के लोकतांत्रिक रूप को ही नुकसान पहुंचाता है। समाज वैज्ञानिक और लोकतंत्र के विचारक इस बात को हमेशा से कहते रहे हैं। यह एक ऐसा सुझाव है, जिसे जनता के वोटों से सत्ता में पहुंचने वाले वर्ग को गांठ बांध लेना चाहिए। भारतीय लोक समाज में तो विशेष रूप से ऐसे लोक उत्सव, लोक अवसर और लोक क्षण बनाए गए हैं, जहां जनता अपने शासकों, मालिकों और सत्ता के विरुद्ध अनेक रूपों में प्रतिरोध दर्ज कराती है और शासक समुदाय उन्हें कहने, सुनने व प्रदर्शित होने का मौका देता है। प्रसिद्ध संस्कृतिवेत्ता मिखाइल वारब्तीन ने ऐसे लोक त्योहारों को समाज के लिए सेफ्टी वॉल्व कहा है, जिसके कारण समाज में विभिन्न समुदाय अपना विरोध, प्रतिरोध और शिकायत दर्ज कराकर भी सहअस्तित्व में रहते हैं। भारतीय समाज में प्रचलित अनेक लोकगीतों, मुहावरों में अपने शासकों और आधिपत्य वाले तबकों के प्रति प्रतिरोध का भाव व्यक्त होता रहता है। ऐसे ही प्रतिरोधों को अपने में जगह देकर भारतीय समाज समाहारी और समरस बन पाता है। आज के दौर में बहुत सी चीजें बदलने लगी हैं। हम दिन-ब-दिन सर्विलेंस समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। आज दफ्तरों, मुहल्लों, कॉलोनियों, यहां तक कि सड़कों को भी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाने की जरूरत पड़ रही है। अभिव्यक्ति के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बायोमेट्रिक्स लगाने का चलन बढ़ रहा है। मशहूर सामाजिक-राजनीतिक चिंतक अगम्बेन ने एक बार सड़क पर छात्रों के साथ खड़े होकर सीसीटीवी लगाने का विरोध किया था। वह मानते थे कि इसके पीछे की धारणा यही दिखती है कि हम अपने हरेक नागरिक को संभावित अपराधी मानते हैं। ये तरीके दुधारी तलवार की तरह होते हैं। इनसे अपराध पर नियंत्रण तो होता है, पर हम प्रतिरोध की आवाज भी दबाते हैं। एक ही तकनीक का सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों तरह से उपयोग किया जा सकता है। महत्वपूर्ण यह देखना होता है कि किस तरह की मंशा इनका उपयोग कर रही है? वैसे तो सर्विलेंस शासन तंत्र का एक तत्व होता है। भारतीय राज्य शासन का इतिहास अगर देखें, तो कौटिल्य ने अपने शासन तंत्र की जो संकल्पना की थी, उसमें भी सर्विलेंस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पर उन्होंने इसका उपयोग अपनी प्रजा के असंतोष और प्रतिरोध को सुनने के लिए भी किया था। प्राचीनकाल में भी जिस राजसत्ता ने प्रतिरोध को सुना, वह सफल और सार्थक हुई। जहां शासक या सत्ता सुनना बंद कर देती है, वहीं समस्याएं पैदा होने लगती है। शासन और शासक के लिए सुनने की कला विकसित करने की जरूरत आज और भी बढ़ती जा रही है। एक अध्ययन के दौरान बनारस के पास मुसहर जाति के एक वृद्ध ने अत्यंत कातर आंखों से एक बार हम लोगों से कहा था- जो अफसर, मालिक, मुख्य लोग हैं, वे या तो हमें ठीक से सुनते नहीं; सुनते हैं, तो समझते नहीं; समझते हैं, तो उल्टा ही करते हैं।

हमें सत्ता और जनता के बीच बढ़ती इस खाई को महसूस करना ही होगा। और यह संभव है, लोकतंत्र में वाद, विवाद और प्रतिरोधों को ठीक से सुन-समझकर और जगह देकर। प्रतिरोध की भी अपनी मर्यादा और सीमाएं होती ही हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

# हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर भारत-चीन के बीच वार्ता शुरू

**इंटरनैशनल डेस्क।**

भारत और चीन के रक्षा मंत्रालयों के बीच हॉटलाइन स्थापित करने पर बातचीत चल रही है। यह बातचीत दोनों देशों के बीच 12 साल पुराने एक रक्षा समझौते को अद्यतन करने और विश्वास बहाली के उपायों के तहत की जा रही है। चीन के रक्षा मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वु कियान ने बताया कि पिछले हफ्ते नई दिल्ली में चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक हुई थी।

उसमें दोनों देशों ने मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बनी अहम सहमति को आगे लागू करने के तरीके पर गहन चर्चा की थी। डोकाला गतिरोध की पृष्ठभूमि में दोनों देशों की सेनाओं सहित भारत-चीन संबंधों के विभिन्न पहलुओं के प्रबंधन के लिए मोदी और जिनपिंग की वुहान में अप्रैल में हुई अनौपचारिक बैठक में सहमति बनी थी। दोनों देशों की सेनाओं के बीच हॉटलाइन को विश्वास बहाली का बड़ा उपाय माना जा रहा है। यह दोनों सेनाओं के मुख्यालयों को सीमा पर गश्त के दौरान तनाव दूर करने और डोकाला जैसे गतिरोध को टालने के लिए बातचीत में तेजी लाने में सक्षम बनाएगा। उन्होंने बताया कि वेई ने सीतारमण को चीन की यात्रा के लिए आधिकारिक आमंत्रण दिया है। वेई की भारत यात्रा के प्रमुख पहलुओं का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय नेताओं के साथ वेई की वार्ता सुरक्षा एवं सैन्य आदान प्रदान और सहयोग मजबूत करने तथा रक्षा विश्वास बहाली उपायों को मजबूत करने पर केंद्रित रहेगी।

# बिम्सटेक सम्मेलन- काठमांडू घोषणा-पत्र जारी, ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर सहमति

**काठमांडो।**

नेपाल के प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली द्वारा बिम्स्टेक की अध्यक्षता श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सीरीसेना को सौंपे जाने के साथ ही संगठन का चौथा शिखर सम्मेलन आज समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बिम्स्टेक के अन्य सदस्य देशों के शीर्ष नेताओं ने नेपाल की राजधानी काठमांडो में आयोजित इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं की बिम्स्टेक प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने की प्रतिबद्धता के साथ यह शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक समाप्त हो गया।'' बिम्स्टेक के मौजूदा अध्यक्ष ओली ने काठमांडो घोषणापत्र का मसौदा पेश किया जिसे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। समापन सत्र को संबोधित करते हुए ओली ने कहा कि शांतिपूर्ण, समृद्ध और स्थिर बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के लक्ष्य को लेकर काठमांडो के घोषणापत्र में साझी बुद्धिमता, सोच और दृष्टि पूरी तरह से दिखती है। बिम्स्टेक के सदस्य देशों में ऊर्जा सहयोग बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक ग्रिड इंटरकनेक्शन की स्थापना के लिए सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर किया गया। ओली ने श्रीलंका को बिम्स्टेक का नया मेजबान देश बनने पर बधाई देने के साथ ही इस शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सदस्य देशों के शासन प्रमुखों/राष्ट्राध्यक्षों को बधाई दी। बिम्स्टेक क्षेत्रीय देशों

का एक समूह है। भारत, बांग्लादेश, म्यामां, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल इसके सदस्य देश हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रिपाला सीरीसेना से मुलाकात की थी।

# डच सासंद ने पैगंबर पर कार्टून प्रतियोगिता लिया वापस, रैली खत्म

**इस्लामाबाद।**

पाकिस्तान में पैगंबर मोहम्मद पर कार्टून प्रतियोगिता आयोजित करने का विवाद थम गया है क्योंकि डच सांसद ने इस प्रतियोगिता को रद्द करने की घोषणा की है। इस प्रतियोगिता के विरोध में पाकिस्तान में हजारों कट्टरवादी जगह-जगह रैलियां और प्रदर्शन कर रहे थे। नीदरलैंड के धुर दक्षिणपंथी विपक्षी नेता ग्रीट विल्डर्स ने कल बताया कि उन्होंने जान से मारने की धमकियों और अन्य लोगों की जान को खतरा होने की इक्षचता की वजह से कार्टून प्रतियोगिता रद्द कर दी। डच सांसद द्वारा कार्टून प्रतियोगिता रद्द करने के बाद पाकिस्तान के धर्मगुरू हुसैन रिजवी को आज अपना मार्च समाप्त करना पड़ा। यह मार्च लाहौर से शुरू हुआ था। इस मार्च का मकसद पाकिस्तान सरकार पर दबाव डालकर नीदरलैंड के साथ राजनयिक संबंध खत्म करना था।

# 2+2 वार्ता से पहले अमरीका ने एच-1बी वीजा को लेकर किया बड़ा ऐलान

**वाशिंगटन।**

अमरीका और भारत के बीच अगले सप्ताह नई दिल्ली में होने वाली 2+2 बैठक से पहले ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि एच-1बी वीजा जारी करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संभावना है कि विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज बैठक के दौरान वीजा का मुद्दा उठा सकती हैं। स्वराज ने पिछले महीने राज्य सभा में बताया था,''हम इस मुद्दे को कई मंचों पर औपचारिक रूप से उठा रहे हैं। हम लोग इस पर व्हाइट हाउस, वहां के राज्य प्रशासन और वहां सांसदों से बात कर रहे हैं। हम नई दिल्ली में छह सितंबर को होने वाली 2+2 बैठक में इस मुद्दे को पूरी विनम्रता से उठाएंगे।'' नाम न जाहिर करने की शर्त पर अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारत एच-1बी वीजा का मुद्दा 2+2 बैठक में उठाने की तैयारी में है लेकिन इसमें कुछ कहने को नहीं रह जाएगा क्योंकि नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। अधिकारी ने बताया कि ट्रंप प्रशासन के कार्यकारी आदेश में अमेरिका में काम करने के लिए अमरीकी वीजा कार्यक्रम की बड़ी पैमाने पर

समीक्षा करने के आदेश दिए गए हैं। वीजा समीक्षा करने का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि इससे अमेरिका के कर्मी और उन्हें मिलने वाला वेतन प्रभावित ना हो। अधिकारी ने बताया कि एच-1बी वीजा जारी करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

## संक्षिप्त समाचार

### अफ्रीका: सशस्त्र संघर्षों में 20 साल में गई 50 लाख बच्चों की जान

**पेरिस।** अफ्रीका में हुए सशस्त्र संघर्षों ने 20 साल में करीब 50 लाख बच्चों की जान ली है। अफ्रीका में 1995 से 2015 के बीच हुए सशस्त्र संघर्षों पर किए गए अध्ययन में यह बात सामने आयी है। अध्ययन में कहा गया है कि सशस्त्र संघर्षों के कारण फैली भूखमरी, चोट और बीमारियों से लगभग 50 लाख बच्चों की मौत हुई जिनमें करीब 30 लाख नवजात हैं। इन शिशुओं की आयु एक वर्ष या उससे कम थी। शोधकर्ताओं के अनुसार पिछले 30 वर्षों में सबसे ज्यादा और भयंकर सशस्त्र संघर्ष अफ्रीकी महाद्वीप में ही हुए हैं। अध्ययन में यह निष्कर्ष आया है कि सशस्त्र संघर्षों के दुष्परिणाम सिर्फ लड़ाकों का घायल होना या उनका मारा जाना नहीं है। बल्कि इसने बच्चों की मौत के खतरे को भी बढ़ा दिया है। इन मौतों का मुख्य कारण गर्भवती महिलाओं को आवश्यक चिकित्सीय उपचार नहीं मिलना, स्वच्छता में कमी होने, स्वच्छ जल की कमी और भोजन की कमी से उत्पन्न कुपोषण इत्यादि हैं।

### अमरीका: बस ट्रक की टक्कर में 7 लोगों की मौत

**न्यू मेक्सिको।** दक्षिण पश्चिम अमरीका के न्यू मेक्सिको शहर में गुरूवार को यात्री बस और एक ट्रक की टक्कर में सात लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी है। पुलिस अधिकारी रे विल्सन ने पत्रकारों को बताया कि इस ट्रक का टायर फट गया था और यह डिवाइडर पार करता हुआ सड़क के दूसरी तरफ सामने से आ रही एक यात्री बस से टकरा गया । यह हादसा थोरियू शहर के समीप रात 12 बजे हुआ। इस बस में 49 यात्री थे। इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। दुर्घटना में बस और ट्रक चालक भी घायल हैं। बस अलबर्क से फीनीक्स जा रही थी। मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड के जांचकर्ताओं की एक टीम सुबह घटनास्थल पर पहुंच गई हैं।

### सीएएटीएसए के तहत देश विशेष आधारित कोई छूट नहीं: अमरीका

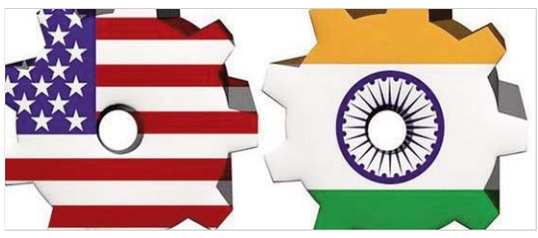

**वाशिंगटन।** ट्रंप प्रशासन का कहना है कि प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिका के दुश्मनों से निपटने का कानून (सीएएटीएसए) के तहत लगने वाले अमेरिकी दंडात्मक प्रतिबंधों से किसी एक विशेष देश को छूट नहीं दी जाएगी।पहचान गुप्त रखने की शर्त पर संवाददाताओं से बातचीत में ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रूस के साथ महत्वपूर्ण रक्षा सौदे करने वाले देशों को छूट देने पर मुद्दा-दर-मुद्दा विचार किया जाएगा। अधिकारी ने कल कहा, किसी एक विशेष देश के लिए पूर्ण छूट की घोषणा नहीं की जाएगी, रूस के साथ महत्वपूर्ण रक्षा सौदे करने के मामले में यदि हम छूट देने पर विचार करेंगे तो वह मुद्दा-दर-मुद्दा तय होगा। और इसके लिए आवश्यक होगा कि उक्त देश रूसी हथियारों पर अपनी निर्भरता को काफी हद तक हम करे। यह पूछने पर कि क्या सीएएटीएसए के तहत भारत को छूट मिलना पक्का है, अधिकारी ने कहा कि हाल ही में अमेरिकी संसद द्वारा संशोधित सीएएटीएसए में किसी देश विशेष के लिए कोई प्रावधान नहीं है। भारत फिलहाल रूस से एस-400 ट्रायम्फ मिसाइल एयर डिफेंस प्रणाली खरीदने की प्रक्रिया में है। इस सौदे के लिए भारत रूस को 4.5 अरब डॉलर की राशि देगा। अधिकारी का कहना है कि ट्रंप प्रशासन सीएएटीएसए लागू करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, हमने भारत सरकार तथा अन्य साझेदारों के साथ सीएएटीएसए पर चर्चा की है। हम इस दिशा में आगे काम कर रहे हैं।

### पाकिस्तान: फिल्मों के 'अश्लील' विज्ञापन पट्टियों पर लगी रोक

**पेशावर।** पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के नये सूचना मंत्री फयज-उल-हसन चौहान ने पंजाब में फिल्मों की'अश्लील'विज्ञापन पट्टियों पर रोक लगा दी है। चौहान ने लाहौर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, पंजाब के सिनेमाघरों में अगर को अश्लील बिल बोर्ड पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो सिनेमाघर को बंद कर दिया जाएगा। यह कैसी इंसानियत है कि आप अर्द्ध नग्न महिला की तस्वीर बड़े बिल बोर्ड पर चिपकाकर प्रदर्शित करते हो। पाकिस्तान के राजनीतिज्ञ और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता अम्मार राशिद ने ट्विटर पर कहा, यह मोरल पुलिसिंग है। चौहान के इस निर्णय से पाकिस्तान के उन लोगों में रोष है जिन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार में कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ रहा है। खान की पार्टी ने पिछले सप्ताह ही श्री चौहान को उनके पद पर नियुक्त किया है।

# चीन छोड़ेगा डेम का पानी, अरुणाचल में बाढ़ का अलर्ट जारी

**ईटानगर।** चीन ने सांगपो नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर भारत को सतर्क किया है क्योंकि इससे निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। यह जानकारी गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश के सांसद निनोंग एरिंग ने दी। चीन में सांगपो के नाम से जानी जाने वाली इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में सियांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। एरिंग ने बताया कि चीन में भारी बारिश के चलते सांगपो नदी में उफान के बाद बीजिंग ने भारत को अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा, 'स्थानीय अधिकारियों ने मुझे बताया कि चीन सरकार ने भारत सरकार से कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में बाढ़ आने की आशंका है। हमने अलर्ट को गंभीरता से लिया है और लोगों को आगाह किया है।' चीन सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार सांगपो/ब्रह्मपुत्र नदी में 9020 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है।

# इमरान खान के फिजुलखर्ची की खुली पोल, घर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हेलिकॉप्टर

**इंटरनैशनल डेस्क।**

पाक के प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान खान ने वादा किया था कि वह प्रधानमंत्री आवास का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही पीएम और मंत्रियों पर होने होने वाले सरकारी खर्च में भी कटौती करेंगे पर लग रहा है कुछ ही दिनों में इमरान अपना ये वादा भूल गए है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हेलिकॉप्टर से घर जाने को लेकर चर्चा का विषय बन चुके हैं। उनपर जनता के पैसे की फिजूलखर्ची का आरोप लग रहा है। 18 अगस्त को ही इमरान खान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी लेकिन इमरान अपने इस वादे को बहुत जल्दी भूल गए। वह पीएम आवास से बानी गाला स्थित अपने घर हेलिकॉप्टर से ही जाते हैं। इसपर जब सूचना मंत्री का कार्यभार संभाल रहे फवाद चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने चौंकानी वाली बात बताई। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि पीएम आवास से घर जाने तक के लिए पीएम जिस हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें सिर्फ 55 पाकिस्तानी रुपये प्रति किमी का खर्च आता है। जबकि रोड से जाने में इससे ज्यादा खर्च आता है। लेकिन सोशल मीडिया पर इमरान के हेलिकॉप्टर से जाने और फवाद के इस बयान के बाद से काफी मजाक बनाया जा रहा है। फवाद का ये भी कहना है कि लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी।

आपको बता दें इस वक्त पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर है। वह जैसे तैसे चीन के दिए कर्ज और अमेरिकी मदद से चल रही है।

# भारत ने लगाई पाक को फटकार, कहा- बार-बार न अलापे कश्मीर राग

**इंटरनैशनल डेस्क।**

कश्मीर मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान की नई सरकार को कड़े शब्दों में कहा है कि उसे वाद-विवाद में शामिल नहीं होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में पाक राजदूत मलीहा लोधी ने बहस के दौरान कश्मीर मुद्दा उठाया तो भारत के अकबरुद्दीन ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई। उन्होंने कहा कि पाक एक असफल दृष्टिकोण को पुनर्जीवित कर रहा है, जिसे विश्व बिरादरी काफी पहले खारिज कर चुकी है। अकबरुद्दीन ने कहा, हमें आशा है कि पाक की नई सरकार व्यर्थ के वाद-विवाद में शामिल होने के बजाय एक सुरक्षित, स्थिर और विकसित दक्षिण एशियाई क्षेत्र के विकास के लिए रचनात्मक रूप से काम करेगी, ताकि यह इलाका हिंसा व आतंक से मुक्त हो सके। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा, मैं पाक को याद दिलाना चाहता हूं कि स्थिर समाधान के लिए सोच में शांति का इरादा और कार्रवाई में शांति संबंधी सामग्री होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अलग-थलग पड़े प्रतिनिधि मंडल ने भारत के अभिन्न हिस्से का बार-बार अनुचित उल्लेख किया है। पाक में बनी नई सरकार के लिहाज से भारत का यह बयान महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रिश्ते चल रहे हैं।

# ट्रंप ने मूलर की जांच को 'अवैध' करार दिया

**वाशिंगटन।**

राष्ट्रपति चुनाव 2016 में रूसी हस्तक्षेप मामलों पर विशेष अभियोजक रॉबर्ट मूलर की जांच को अवैध बताते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी जांच का दायरा मेरे करीबियों से आगे बढ़ ही नहीं रहा है। ट्रंप ने बृहस्पतिवार को ब्लूमबर्ग न्यूज को दिये गए साक्षात्कार में कहा कि 2016 के उनके चुनाव अभियान के साथ रूस के कथित सांठगांठ की जांच करने के लिए पिछले साल हुई मूलर की नियुक्ति गलत थी।उन्होंने ब्लूमबर्ग को बताया, मैं इसे अलग तरह से देखता हूं। मैं इसे एक अवैध जांच की तरह देखता हूं।'' समाचार एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कुछ च्चमहान विद्वानों'' का हवाला दिया जो कहते हैं कि ''विशेष अभियोजक कभी होना ही नहीं चाहिए था।'' कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने विशेष अभियोजकों के संबंध में विशिष्ट कानून के अभाव में न्याय मंत्रालय द्वारा जांच के लिए एफबीआई के पूर्व निदेशक मूलर का नाम सुझाने पर सवाल उठाए थे। गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन का अपना न्याय मंत्रालय कहता है कि यह वैध है। इससे पहले अगस्त की शुरुआत में ट्रंप के पूर्व राजनीतिक सलाहकार रोजर स्टोन के सहयोगी रहे एंड्र्यू मिलर ने अपीलीय अदालत में मूलर की नियुक्ति की वैधता को चुनौती दी थी। मिलर को मूलर अधिकृत ग्रांड जूरी के समक्ष स्टोन के संबंध में गवाही देने के लिए हाजिर होना है। मिलर के मामले को समर्थन दे रहे नेशनल लीगल एंड पॉलिसी सेंटर का तर्क है कि 17 मई, 2017 को हुई मूलर की नियुक्ति, संविधान का उल्लंघन है क्योंकि यह नियुक्ति अटॉर्नी जनरल जेफ सेशन्स की बजाए डिप्टी अटॉर्नी जनरल रॉड रॉजन्टीन के द्वारा की गई।

# पनबिजली परियोजनाओं के निरीक्षण के लिए भारत ने पाक विशेषज्ञों को किया आमंत्रित

**लाहौर।**

भारत ने चेनाब नदी पर पनबिजली परियोजनाओं स्थलों का दौरा करने के लिये पाकिस्तानी विशेषज्ञों को अगले आमंत्रित किया है। इसका मकसद परियोजनाओं को लेकर उनकी चिंता दूर करना है। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। हालांकि पाकिस्तान की आपत्ति के बावजूद भारत उस पर काम जारी रखने का संकेत दिया है। सिंधु जल संधि पर दो दिवसीय उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता पूरी होने के बाद इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात भारत और पाकिस्तान के बीच पहली आधिकारिक बातचीत में भारत ने चेनाब नदी पर 1,000 मेगावाट क्षमता की पाकल दुल और 48 मेगावाट की लोअर कालनाई पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण को लेकर पाकिस्तान की आपत्तियों को खारिज कर दिया। अधिकारी ने कहा कि भारत ने दोनों पनबिजली परियोजनाओं पर काम जारी रखने का संकेत दिया है। पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव एस अहमद ख्वाजा ने समाचार पत्र डान से कहा, ''लाहौर में दो दिन की बातचीत की यह बड़ी सफलता है कि भारत ने परियोजना स्थलों पर हमारे विशेषज्ञों को आने की अनुमति दी है।

इसीलिए हमारे विशेषज्ञ अगले महीने के अंत तक भारत की यात्रा करेंगे।उन्होंने कहा कि हमारे विशेषज्ञ परियोजना स्थल का निरीक्षण करेंगे और यह देखेंगे कि सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) के तहत निर्माण हो रहा है कि नहीं।

# पार्षद नेन्सी सुमरा के पिता को न्यायिक हिरासत में भेजा

**तीन दिन का रिमांड खत्म होने पर एसीबी ने कोर्ट में किया था पेश**

सूरत. अवैध निर्माण को लेकर 55 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार भाजपा पार्षद नेन्सी सुमरा के पिता मोहन सुमरा का शुक्रवार को तीन दिन का रिमांड खत्म होने पर कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के हाथों नेन्सी सुमरा के भाई प्रिंस सुमारा के रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद पुलिस मोहन सुमरा को खोज रही थी, तभी मोहन सुमरा ने खुद समर्पण पर कर दिया था। जांच अधिकारी की ओर से मोहन सूमरा को कोर्ट में पेश किए जाने पर कोर्ट ने तीन दिन का रिमांड मंजूर कर लिया था। शुक्रवार को रिमांड की अवधि पूरी होने पर उसे कोर्ट में पेश किया गया। जांच अधिकारी की ओर से अतिरिक्त रिमांड की मांग नहीं करने पर कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। गौरतलब है कि पार्षद नेन्सी सूमरा के पिता मोहन और भाई प्रिंस सूमरा पर आरोप है कि अवैध निर्माण के लिए परेशान नहीं करने पर 75 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इसमें से 20 हजार रुपए उन्होंने ले लिए थे, लेकिन बचे 55 हजार रुपए को लेकर उस व्यक्ति ने पिता-पुत्र के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत की थी। ब्यूरो के अधिकारियों ने 22 अगस्त को जाल बिछाकर प्रिंस सूमरा को 55 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा था, जबकि उसके पिता मोहन सूमरा मौके से फरार हो गया था।

# आंदोलन के समर्थन में पाटीदारों का शांति हवन

**पूणागांव की सम्राट सोसायटी में उमड़े पाटीदार**

सूरत. पूणागांव सम्राट सोसायटी की वाडी में शुक्रवार को कांग्रेस पार्षद की अगुवाई में पाटीदारों ने शांति हवन का आयोजन कर हार्दिक पटेल के उपवास आंदोलन का समर्थन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पाटीदार मौजूद थे।

आरक्षण, किसानों का कर्ज माफ और युवाओं की रोजगार की मांग के साथ हार्दिक पटेल 25 अगस्त से अनशन पर है और विभिन्न शहर तथा गांवों से उसे समर्थन मिल रहा है। सूरत में भी रोजाना समर्थन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन पाटीदारों की ओर से किया जा रहा है। इसी के तहत शुक्रवार को पूणागांव सम्राट सोसायटी की वाडी में कांग्रेस पार्षद धीरज लाठियां की अगुवाई में शांति हवन का आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया शांति हवन के जरिए हार्दिक पटेल के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करने का साथ ही आंदोलन का समर्थन किया गया। वहीं राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार अल्पेश कथीरिया की मुक्ति की मांग को भी दोहराया गया।

# ससुर और जेठ को नहीं मिली जमानत

**अन्य दो की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज, कोर्ट बिल्डिंग से कूद कर विवाहिता के जान देने का मामला**

सूरत. कोर्ट बिल्डिंग से कूद कर विवाहिता के आत्महत्या करने के मामले में गिरफ्तार ससुर और जेठ की नियमित और अन्य दो अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को सेशन कोर्ट ने नामंजूर कर दी।

घरेलू हिंसा प्रकरण की सुनवाई के लिए 21 जुलाई को अठवालाइंस स्थित कोर्ट में आई विवाहिता सिम्पीसिंह राजपूत (30) ने बिल्डिंग की नौवीं मंजिल से छलांग लगा दी थी। आत्महत्या की घटना क को लेकर जांच में जुटी उमरा पुलिस ने मृतका के भाई बिपीनसिंह की शिकायत पर दस जनों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर पति विजयकुमार, जेठ अजयकुमार, ससुर मुरलीधर राजपूत, जेठानी बबीता अजयकुमार और सास मालतीदेवी राजूपत को गिरफ्तार कर लिया था। न्यायाकि हिरासत में कैद अभियुक्तों में से ससुर मुरलीधर शितलाप्रसाद राजपूत और जेठ अजयकुमार मुरलीधर राजपूत ने नियमित जमानत के लिए कोर्ट से गुहार लगाई थी, जबकि मृतक की ममेरी सास इंद्रवतीदेवी अरविंदकुमार राजपूत और उसके पुत्र करमवीरसिंह अरविंदसिंह राजपूत ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान लोकअभियोजक दीगंत तेवार और अधिवक्ता किरीट पानवाला ने दलीलें पेश कर जमानत याचिकाओं का विरोध किया। शुक्रवार को अंतिम सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को ध्यान में रखते हुए चारों अभियुक्तों की जमानत याचिकाएं नामंजूर कर दी। गौरतलब है कि बमरोली क्षेत्र निवासी सिम्पीसिंह राजपूत की शादी लिंबायत मयूर सोसायटी निवासी बैंक कर्मी विजयसिंह राजपूत के साथ हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद से ही सिम्पीसिंह को प्रताड़ित किए जाने पर वह पीहर आ गई थी और ससुरालवालों के खिलाफ कोर्ट में घरेलु हिंसा की शिकायत की थी। इसी मामले की सुनवाई के दौरान सिम्पी ने कोर्ट बिलंडिग की नौवीं मंजिल से छलांग लगा दी थी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

# कपड़ा व हीरा व्यापारियों से लाखों की धोखाधड़ी

सूरत. सलाबतपुरा व वराछा में कपड़ा व हीरा व्यापारियों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी के दो अलग अलग मामले दर्ज हुए है। सलाबतपुरा पुलिस के मुताबिक रिंग रोड स्थित लक्ष्मी टेक्सटाइल मार्केट के सुरेश प्रजापति, दलाल प्रकाश प्रजापति व प्रेमसिंह राजपूत ने मिल कर कतारगाम शांतिनगर सोसायटी निवासी कपड़ा व्यापारी संजय रोकड़ के साथ धोखाधड़ी की। गत१७ मार्च से ३० मार्च के दौरान उन्होंने बीस दिन में भुगतान का वादा कर संजय व अन्य व्यापारियों से ४१ लाख ३५ हजार ४६८ रुपए का ग्रे कपड़ा उधार लिया लेकिन उसका भुगतान नहीं कर धोखाधड़ी की।

वराछा पुलिस के मुताबिक मोटा वराछा साईं मिलन अपार्टमेंट निवासी तुषार सवाणी ने वेड रोड केशव पार्क सोसायटी निवासी हितेश घोरी के साथ धोखाधड़ी की। मीना बाजार स्थित सरदार डायमंड मार्केट में हीरे का कारोबार करने वाले हितेश से २७ अगस्त को मिला। उसने ग्राहक होने की बात बता कर दलाली पर बेचने के लिए ६६ लाख ३९ हजार ७५६ रुपए के ३५४.८९ कैरेट तैयार हीरे लिए। लेकिन उनका भुगतान नहीं किया और न ही हीरे लौटाए। इस पर हितेश ने गुरुवार को वराछा थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई।

# गोल्ड मेडल विजेता सरिता गायकवाड़ को 1 करोड़ का पुरस्कार देने की घोषणा

**गुजरात का गौरव बढ़ाने वाली सरिता को मुख्यमंत्री ने दी बधाई**

अहमदाबाद। मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने जकार्ता में चल रहे 18वें एशियाई खेलों में महिलाओं की रिले दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर गुजरात का गौरव बढ़ाने वाली डांग जिले की वनबंधु कन्या सरिता गायकवाड़ को खेल प्रतिभा पुरस्कार के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। सरिता गायकवाड़ को बधाई देते हुए रूपाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गुजरात में शुरू किए गए खेल महाकुंभ के चलते ऐसे होनहार खिलाड़ियों को वैश्विक स्तर पर गुजरात और भारत का नाम रोशन करने का अवसर मिला है। इसके अलावा स्थानीय विधायक मंगलभाई गावित ने एक महीने का वेतन सरिता गायकवाड को पुरस्कार स्वरूप देने की घोषणा की है। बता दें कि दक्षिण गुजरातके डांग जिले की आहवा तहसील के कराडी गांव निवासी और खेत मजदूरी करनेवाले लक्ष्मभाई की पुत्री सरिता गायकवाड ने एशियन खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया है।

डांग जिले में वर्ष 2012 में हुए खेल महाकुंभ में सरिता ने एक साथ पांच स्पर्धा में एन्ट्री लेकर पांचों में जीत दर्ज की थी। सरिता लक्ष्मणभाई गायकवाड ने कॉलेज के एक कोच की सलाह पर एथ्लेटिक्स को चुना था7 परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के बीच सरिता ने यूनिवर्सिटी स्तर के स्पर्धा में गोल्ड समेत तीन गोल्ड मेडल जीते थे। 2017 में आंध्र प्रदेश में हुई नेशनल इंटर स्टेट सिनियर एथ्लेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेकर 400 मीटर दौड़ में ब्रोंज मेडल जीता था।

# 74 फीसदी रोजगार निर्माण के साथ गुजरात देश में अव्वल: मुख्यमंत्री

**कलोल में मेगा जॉब फेयर का उद्घाटन: 1700 युवाओं को मिले रोजगार के अवसर**

अहमदाबाद। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि गत 15 वर्षों से रोजगार प्रदान करने के मामले में गुजरात अव्वल है। उन्होंने कहा कि समग्र देश में रोजगार कार्यालयों के जरिए दिए जाने वाले रोजगार में गुजरात अकेला 74 फीसदी रोजगार उपलब्ध कराता है। गांधीनगर जिले के कलोल में शुक्रवार को कलोल तालुका केळवणी मंडल और गुजरात यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मेगा जॉब फेयर के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने यह बात कही।

इस जॉब फेयर के जरिए एक ही छत के नीचे एक साथ 1700 युवाओं को रोजगार अवसर मुहैया कराने के उपक्रम की उन्होंने सराहना की और विश्वास जताया कि इससे युवाओं के माता-पिता और परिवार के सपने साकार होंगे। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने सीआई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल के सभागार का भी उद्घाटन किया। रूपाणी ने युवा शक्ति को व्यापक रोजगार अवसर मुहैया कराने के लिए विनिर्माण क्षेत्र के साथ सेवा क्षेत्र को भी शामिल करने की मंशा जताई है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि देश की कुल आबादी में 18 से 35 वर्ष की उम्र के युवाओं की 55 फीसदी भागीदारी के साथ भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। राष्ट्र और राज्य की संपत्ति समान इस युवा शक्ति को शिक्षा से सुसज्जित कर उसे योग्य रोजगार देने का दायित्व सरकारों को निभाना है। सेवा क्षेत्र में हॉस्पिटालिटी, बैंकिंग और सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों को रोजगार सृजन में जोड़ना है। उन्होंने कहा कि गुजरात में हर हाथ को काम, हर खेत को पानी के मंत्र के साथ इस सरकार ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर सुनहरे करियर की नई दिशा दिखाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात में वाइब्रेंट समिट की सफलता और नीति संचालित राज्य होने के कारण युवा शक्ति को काम-रोजगार उपलब्ध कराने में सफलता मिली है। उन्होंने राज्य की जीआईडीसी बसावटों में बड़े उद्योगों के साथ-साथ लघु एवं मझोले उद्योगों के भी स्थानीय रोजगार के सक्षम माध्यम बनने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रति वर्ष मेगा जॉब फेयर आयोजित कर उद्योग गृहों में स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने को संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में गारमेंट और एपरल पॉलिसी के अंतर्गत महिला रोजगार को प्रोत्साहन देने को महिला कारीगरों के लिए 4 हजार रुपए की पे रोल सहायता सरकार चुकाती है। इसके चलते नारी शक्ति को भी रोजगार के व्यापक अवसर मिले हैं।

रूपाणी ने रोजगार सृजन की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में निजी क्षेत्र के साथ-साथ सरकारी सेवाओं में भी पारदर्शी तरीके से युवा शक्ति की भर्ती कर गत वर्ष 72 हजार युवाओं को सरकारी सेवा में शामिल किया है।

इस वर्ष 17 हजार अतिरिक्त युवाओं को सरकारी सेवा का अवसर देंना है। उन्होंने कहा कि राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं को इस तरह से नौकरी उन्मुख बनाना है कि यहां से शिक्षा-दीक्षा हासिल कर निकलने वाले युवा को जल्द ही व्यवसाय-रोजगार मिल जाए। इस संदर्भ में उन्होंने गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (जीएफएसयू), रक्षा शक्ति और पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी का दृष्टांत पेश किया।

केळवणी मंडल और नवनिर्मित सभागार के दाताओं तथा युवाओं को नियुक्तियां देने वालों का मुख्यमंत्री ने सम्मान किया। गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) के अध्यक्ष बलवंतसिंह राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में गुजरात में रोजगार निर्माण के क्षेत्र में 2028 तक आगामी दशक की योजना बनाई जा रही है। राज्य के युवाओं को उद्योगों में रोजगार अवसर देने के लिए जीआईडीसी एस्टेट के योगदान की उन्होंने सराहना की। गुजरात यूनिवर्सिटी के कुलपति हिमांशु पंड्या ने मेगा जॉब फेयर की रूपरेखा के साथ कहा कि कौशल आधारित मानवबल का डेटाबेस तैयार हो रहा है।

# पास नेता हार्दिक की तबियत और बीगड़ी : अनशन जारी

अहमदाबाद। पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के मुख्य संयोजक हार्दिक पटेल ने पाटीदारो को आरक्षण और गुजरात के किसानो की संपूर्ण कर्ज माफी को लेकर शुरु किए अनशन का आज सातवां दिन रहा। हार्दिक पटेल की तबियत अब दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। गुरुवार के दिन ही हार्दिक पटेल ने जल का भी त्याग कर दिया था। जल का त्याग करने से उनकी किडनी और हृदय पर प्रतिकुल असर पड़ रहा है। सास लेने में भी तकलीफ हो रही है। अनशन के चलते हार्दिक पटेल का वजन अब तक साढ़े चार किलो से भी अधिक घट चुका है। आज अनशन के सातवें दिन हार्दिक पटेल की तबियत और अधिक खराब हो गई है। तबियत खराब हो रही है फिर भी हार्दिक ने अपने अनशन जारी रखे हैं।

दुसरी ओर पाटीदार समाज के लोगों की ओर से भी अपील की जा रही है। पास की ओर से लीडर निखील सवाणी ने सोला पुलिस स्टेशन में अर्जी दायर की है और हार्दिक के हेल्थ मोनिटरींग के लिए एम्ब्युलन्स रखने की मांग की है। हार्दिक के उपवास आंदोलन के समर्थन में बहुत से समुदाय के लोग पहुंच रहे है। आज भी यह सील सीला जारी रहा। दुसरी ओर हार्दिक के समर्थन में अब अलग अलग समाज के लोग भी आगे आ रहे हैं। अहमदाबाद के सोला-घुमा, मारुती नंदन मंदिर, वैष्णोदेवी सर्कल, देत्रोज के राधा-क्रिष्न मंदिर स्थल पर हार्दिक के समर्थन में प्रतिक उपवास और रामधून समेत के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दुसरी ओर आज अनशन के सातवें दिन हार्दिक पटेल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि किसानो की संपूर्ण कर्जमाफी और आरक्षण को लेकर वह अन्न और जल त्याग कर चुका है। हार्दिक ने लडाई लंबे समय तक जारी रखने की बात की है। हार्दिक ने कहा है कि वे अब गांधी के मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सरकार जीतेगी या महात्मा जीतेंगे यह बात अब साबित होगी। दुसरी ओर मुस्लिम समाज के लोगों की ओर से भी शहर के माणेकचोक इलाके में हार्दिक के आरोग्य को लेकर नमाज अदा की गई। पिछले २४ घंटे में ही हार्दिक पटेल का वजन ९०० ग्राम से अधिक घट गया है। हार्दिक के मेडिकल चेकअप पर नजर रखनेवाले डॉक्टर नम्रता ने बताया है कि हार्दिक ने शुक्रवार से ही प्रवाही लेना भी बंद कर दिया है जिसके चलते समस्या और अधिक बढ़ सकती है।

# बुलेट ट्रेन का साबरमती स्टेशन बनाने के लिए स्पर्धा

अहमदाबाद अगस्त। नेशनल हाईस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशन की योजना अहमदाबाद-मुंबई का पहेला स्टेशन अहमदाबाद का साबरमती स्टेशन रहेगा। यह बात कोई नई नहीं है किन्तु स्टेशन को मोडल टर्मिनल बनाने के लिए १६ कंपनीओ की ओर से इच्छा व्यक्त की गई है। मोदी के महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट में प्रतिष्ठा की जंग शुरु हो चुकी है। जिसे लेकर अलग अलग १६ कंपनिया मेदान में आ चुकी है। बुलेट ट्रेन का साबरमती स्टेशन बनाने के लिए कंपनीओ की ओर से स्पर्धा चल रही है। साबरमती रेलवे टर्मिनल अहमदाबाद से मुंबई की बुलेट यात्रा का पहला स्टेशन होगा जो महात्मा गांधी की दांडीमार्च थीम पर आधारित रहेगा। सूत्रो की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक साबरमती रेलवे टर्मिनल अहमदाबाद से मुंबई की बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन होगा। जो महात्मा गांधी की १९३० की ऐतिहासिक दांडी मार्च पर आधारित होगा। स्टेशन का काम अगले साल नवम्बर महिने में शुरु होगा। अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन की कार्रवाई की समीक्षा के लिए दिल्ली से अधिकारियों की टीम अहमदाबाद पहुंच चुकी है। यह टीम ने सभी पहलुओं पर अभ्यास करते हुए देश की पहली बुलेट ट्रेन के बारे में पुरी जानकारी प्रस्तुत की थी। बुलेट ट्रेन के रास्ते में आने वाले सभी पैड काटने के बदले रिप्लान्ट किये जाएंगे। जो किसान कीमत की मांग कर रहे है उन्हे कीमत दी जाएगी और जहां पैड काटे जाएंगे उन पैडो को फिरसे लगाने की बात भी की जा रही है। बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से रवाना होने के बाद आणंद स्टेशन से १० किलोमीटर अंतर से निकलेगी। ट्रेन सुरत भी स्टेशन के निकट नहीं पहुंचेगी। किम के निकट दिशा बदलती हुई पूर्व में पहुंचेगी और बिलीमोरा में कोसाली में स्टेशन बनाया जाएगा। १० कोच की बुलेट ट्रेन १८ कलाक चलेगी और ३५ अप और डाउन की फ्रिक्वन्ची होगी। अप में ३५ और डाउन में भी ३५ बार दोडाई जाएगी।

महादेव मीडिया
रोहताश यादव 9924144499, 7015339195
वीजिटिंग कार्ड, बिल बुक, लेटर पैड, बेनर, पोस्टर, आदि का डिजाइन बनवाने के लिए संपर्क करें। (हिन्दी, गुजराती)
हिन्दी, गुजराती न्युज पेपर डिजाईन करवाने के लिए संपर्क करें।
304 केवल कॉम्पलेक्ष नवा गाम, डिंडोली, उधना सूरत।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com